आर. एच. प्रयोगशालाएँ और एक और बनाम राजीव मुकुल
एकल स्वामी। (न्यामूर्ति एम. एम. एस बेदी)

न्यामूर्ति एम. एम. एस. बेदी केसमक्ष
आर. एच. प्रयोगशालाएँ और ए. एन. आर.-याचिकाकर्ता
बनाम
राजीव मुकुल सोल प्रोप.,- प्रतिवादी
सी. आर. संख्या **2011 का 7264**
10 फरवरी, 2012।

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 227 – सिविल प्रक्रिया संहिता- नियम 20 - आदेश VII नियम 11 – कॉपीराइट्स एक्ट, 1957 - धारा 51, 55 & 62 & 62(2) – व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 – धारा 27(2), 134, 134(2)&135 – वादी ने 1999 अधिनियम की धारा 27 (2) के साथ 134 और 135 और 1957 के अधिनियम धारा 51 और 55 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए सिविल मुकदमा दायर किया की प्रतिवादी को दवा चिह्न "OMEEZY" के तहत विपणन और दवा तैयार करने से रोकने से रोका जाए यह आरोप लगाते हुए की वादी के व्यपार चिन्ह “OMEZEE" के पारित होने बराबर है प्रतिवादी ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन दायर किया– ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज – चुनौती पुनरीक्षण में – पुनरीक्षण ने यह मानते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता विपणन में लिप्त था और आक्षेपित व्यापार चिह्न "OMEEZY" के तहत करनाल जिले निर्यात किया गया था। करनाल में अदालत को क्षेत्राधिकार होगा।

आयोजित, ऊपर पुनरुत्पादित प्रावधानों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा134 उस जिले की व्याख्या करती है जो पंजीकृत व्यापार चिह्न के उल्लंघन या पंजीकृत व्यापार चिह्न में किसी भी अधिकार के लिए प्रासंगिक या प्रतिमुकदमाी द्वारा किसी भी व्यापार चिह्न के उपयोग से उत्पन्न होने वाले मुकदमे में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा जो मुकदमाी के व्यापार चिह्न के

समान या भ्रामक रूप से समान है, चाहे वह पंजीकृत हो या अपंजीकृत।कॉपीराइट अधिनियम की धारा62 किसी भी अन्य कार्य में कॉपीराइट के उल्लंघन या कॉपीराइट अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के मामलों में जिला न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा134 (2) में उपयोग किया गया शब्द शामिल है, और कॉपीराइट अधिनियम की धारा62 (2) इस तथ्य का संकेत है कि धारा134 (2) और धारा62 (2) के तहत निर्धारित जिला न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित अधिकार क्षेत्र से अधिक व्यापक है।

(पैरा 13)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा134 प्रक्रियात्मक प्रकृति की है और उक्त धारा को शामिल करने का उद्देश्य व्यापार चिह्नों से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को प्रतिवादी के स्थान पर जाने और वहां मुकदमा दायर करने के बजाय अपने स्थान पर मुकदमा दायर करने में सहायता करना था।सी. पी. सी. की धारा20 का दायरा ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा134 (2) और कॉपीराइट अधिनियम की धारा62 (2) द्वारा बढ़ाया गया है।

(पैरा 18)

आगे अभिनिर्धारित किया कि वादी-प्रतिवादी के वाद का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रतिवादी संख्या 1, विपणन में लिप्त है और कॉपीराइट अधिनियम के तहत वादी/प्रतिवादी के अधिकारों के उल्लंघन के अलावा, करनाल जिले में विवादित व्यापार चिह्न OMEEZY का निर्यात कर रहा है। आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदनकोअस्वीकृतकरनेकेलिए आवेदन, क्षेत्रीय अधिकार की कमी के वाद की अस्वीकृति के लिए आधार नहीं माना जा सकता है जैसा कि यूफार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड और अन्य (ऊपर) के मामले में निर्धारित गया है।

(पैरा 19)

देवेश कुमार, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की ओर से

अरविंद सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

न्यामूर्ति एम. एम. एस. बेदी

(1) प्रतिवादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी है, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, जिसमें प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के अभाव में वादी -प्रतिमुवादी के मुकदमे को खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत प्रतिमुकदमी-याचिकाकर्ता संख्या 1 के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

(2) समग्र और संक्षिप्त रूप से, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के लिए आत्यन्तिक रूप आवश्यक प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि मैसर्स ज़ी लेबोरेटरी, उचानी, जी. टी. करनाल रोड, हरियाणा के मालिकों के रूप में वादी-प्रत्यर्थी ने ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा134 और 135 के साथ पठित धारा27 (2) और कॉपी राइट्स अधिनियम, 1957 की धारा51 और 55 के तहत एक मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह से दवा के निशान ओ. एम. ई. ई. ई. जेड. वाई. के तहत दवा के निर्माण और विपणन पर रोक लगाने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री दायर की गई थी।

यह वादी के व्यापार चिह्न "ओ. एम. ई. ई. जेड. ई". के रूप में पारित करने और अभियोक्ता-प्रतिवादी के व्यापार चिह्न के लिए मामले में भ्रामक होने और व्यापार चिह्न ओ. एम. ई. ई. ई. जेड. वाई. द्वारा किए गए लाभों के संबंध में खातों के प्रत्यर्पण की परिणामी राहत के साथ अभियोक्ता के व्यापार चिह्न की नकल के तहत आच्छादित समानता के बराबर है। वादी ने शिकायत में दावा किया था कि यह एक एकल स्वामित्व वाली फर्म है जिसका नाम और शैली मेसर्स ज़ी प्रयोगशाला है और जो करनाल में अपनी विनिर्माण गतिविधियों का संचालन करती है और वादी - प्रतिवादीकातैयार रचना भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर बेची जाती है और

उचित रूप से लागत प्रभावी और राहत देने वाली तैयारी के रूप में निर्भर हैं और इसकी विनिर्माण सुविधाएं विधिवत ISO 9001:2000 जीएमपी के रूप में प्रमाणित हैं।

(3) वादी का दावा है कि उसने अप्रैल 2004 में अपनी दवा की तैयारी के संबंध में व्यापार चिह्न "OMEZEE"की कल्पना की थी और उसे अपनाया था और उक्त व्यापार चिह्न का उपयोग अप्रैल 2004 के महीने से हरियाणा प्रशासन के निदेशक नियंत्रक के कार्यालय द्वारा दवा और सौंदर्य प्रसाधन के प्रावधानों के तहत जारी वैध और मौजूदा लाइसेंस के तहत एक दवा के निर्माण के लिए किया जा रहा है और वादी के पास जॉर्जिया के दवा प्राधिकरण द्वारा जारी दवा लाइसेंस 10.8.2004 से था।

(4) चिकित्सा पेशे, औषधि उद्योग और बड़े पैमाने पर आम जनता की नजर में एक अनूठी प्रतिष्ठा और मूल्यवान सद्भावना हासिल करने वाले व्यापार चिह्न "ओ. एम. ई. जेड. ई. ई". को देखते हुए और उक्त सामान विशेष रूप से वादी से जुड़े हैं।वादी का दावा है कि वह व्यापार चिह्न "OMEZEE"का व्यापक और पूर्व उपयोगकर्ता है, जबकि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता संख्या 2 विनिर्माण कर रहा है और प्रतिवादी -याचिकाकर्ता संख्या 1 भ्रामक व्यापार चिह्न "OMEEZY"के तहत समान उत्पादों का विपणन कर रहा है, जो वादी के व्यापार चिह्न के समान है, जिसका दुर्भावनापूर्ण इरादा वादी के व्यापार चिह्न का उल्लंघन करने और वादी और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का है।प्रतिवादी -याचिकाकर्ता संख्या 2 ने इस याचिका पर जवाब दायर किया है कि ट्रेड मार्क "OMEZEE"को 20.11.2008 पर अपनाया गया है और प्रतिवादी ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा12 के तहत संरक्षित होने के हकदार हैं और ट्रेड मार्क "OMEZEE"कैप्सूल का ईमानदार सहमत उपयोगकर्ता होने के नाते, लेकिन प्रतिअभियोक्ता-याचिकाकर्ता संख्या 1 ने वादीकेआवेदन को अस्वीकृति करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि "OMEEZY"कैप्सूल का निर्माण मैसर्स आरएच लैबोरेटरीज पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है और लाइसेंस को ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन, सोलन एच. पी. के कार्यालय द्वारा

अनुमोदित किया गया है और लाइसेंस को केवल निर्यात के लिए चिह्नित किया गया था और इस संबंध में ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी का अनुमोदन पत्र था।

यह दावा करतेहुएकि कथित कैप्सूल जॉर्जिया में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बेचे जा रहे हैं।प्रतिवादी संख्या 1 ने आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन में यहतर्कलियाकि न तो "ओ. एम. ई. जेड. ई. ई". कैप्सूल का निर्माण करनाल में किया जा रहा है और न ही इसे अदालत के अधिकार क्षेत्र में बेचा जा रहा है।इस प्रकार, वादी के पास वाद समर्थकारणनहीं है और न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है और इस प्रकार, शिकायत को खारिज किया जा सकता है।

(5) यह अपंजीकृत व्यापार चिह्नों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई का मामला है लेकिन धारा27 (2) याचिकाकर्ता को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वस्तुओ को किसी अन्य व्यक्ति के वस्तुओके रूप में देने के लिए कार्रवाई का अधिकार देती है।

(6) विवादित आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था प्रतिवादी-याचिकाकर्ता संख्या 2, एस. आई. ए. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में, जो करनाल में प्रतिवादी-याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा निर्मित अपने उत्पादों के विपणन के लिए उल्लंघन किए गए चिह्न का उपयोग कर रहा है, करनाल की अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा।

(7) यहां यह देखना अनुचित नहीं है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता संख्या 1 एस. आई. ए. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस तरह का आवेदन दायर करके अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन याचिकाकर्ता No.2-प्रतिवादीसंख्या 2, विवादित आदेश के खिलाफ प्रतिवादी-याचिकाकर्ता संख्या 1 में शामिल हो गया है।

(8) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि थोड़ा हाउस और पटेल फील्ड मार्शल इंडस्ट्रीज बनाम एजकेमांगीऔर पी. एम. डीजल लिमिटेड (1) में दिएनिर्णय की ठीक से सराहनानहींकीगईहै। यह तर्क दिया गया है कि अधिकार

क्षेत्र में कोई दोष, चाहे वह आर्थिक हो या क्षेत्रीय, किसी भी डिक्री को पारित करने के लिए न्यायालय के अधिकार पर हमला करता है और इस तरह के दोष को पक्षों की सहमति से भी ठीक नहीं किया जा सकता है।प्रतिवादी याचिकाकर्ता संख्या 2, भले ही उसने करनाल में अधिकार क्षेत्र के लिए सहमति दी हो, यदि कोई आदेश अंततः पारित किया जाता है तो वह क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण अमान्य होगा।

(9) मैंने याचिकाकर्ताओं के वकील को सुना है और यह निर्धारित करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया है कि क्या ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 के प्रावधानों को देखते हुए, करनाल के न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र होगा और क्या शिकायत आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत खारिज किए जाने के योग्य है। वादी-प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा134 और 135 के साथ पठित खंड 27 (2) के और

---

(1) 2006 (32) पीटीसी 1 (एससी)

1999, और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 और 55, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पासिंग ऑफ के उल्लंघन को रोकने और खातों को प्रस्तुत करने और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायरकियागयाहै।

धारा 7 (2) इस प्रकार हैः-

"27. अपंजीकृत व्यापार चिह्न के उल्लंघन के लिए कोई कार्रवाई नहीं।-

(1) किसी भी व्यक्ति को अपंजीकृत व्यापार चिह्न के उल्लंघन को रोकने या नुकसान की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं होगा।

(2) इस अधिनियम की कोई भी बात किसी व्यक्ति के खिलाफ वस्तुओं या सेवाओं को किसी अन्य व्यक्ति के वस्तु के रूप में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा

प्रदान की गई सेवाओं के रूप में या उसके संबंध में उपचार के लिए कार्रवाई के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है।

(10) उपर्युक्त धारा के अवलोकन से संकेत मिलता है कि धारा 27 (1) किसी भी व्यक्ति को अपंजीकृत व्यापार चिह्न के उल्लंघन के लिए निषेधाज्ञा और नुकसान की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने से रोकती है, लेकिन जहां तक धारा 27 (2) का संबंध है, यह किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के वस्तुओं के रूप में वस्तुओं को पारित करने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के अपने अधिकार को प्रभावित करने से नहीं रोकती है।वर्तमान मुकदमा OMEEZYके नाम से माल को बेचने के लिए दायर किया गया है क्योंकि यह वादी-प्रतिवादी व्यापार चिह्न OMEEZYको हटाने के बराबर है। जहाँ तक पंजीकृत व्यापार चिह्न के उल्लंघन या पारित करने के लिए मुकदमे के लिए अधिकार क्षेत्र का संबंध है, धारा 134 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करती है और जहाँ तक उल्लंघन या पारित करने के लिए मुकदमों में राहत का संबंध है, धारा 134 निम्नानुसार हैः

"134.उल्लंघन आदि के लिए मुकदमा जिला न्यायालय के समक्ष दायर किया जाएगा।-

(1) मुकदमानहीं

(ए) पंजीकृत व्यापार चिह्न के उल्लंघन के लिए; या

(बी) पंजीकृत व्यापार चिह्न में किसी अधिकार से संबंधित; या

(सी) प्रति वादी द्वारा किसी भी व्यापार चिह्न के उपयोग से उत्पन्न होने के लिए कोई मुकदमा, जो अभियोक्ता के व्यापार चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है, चाहे वह पंजीकृत हो या अपंजीकृत, मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले जिला न्यायालय से हीन किसी भी न्यायालय में स्थापित किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के खंड (क) और (ख) के प्रयोजन के लिए, "अधिकार क्षेत्र रखने वाला जिला न्यायालय", सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या उस

समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, स्थानीय सीमाओं के भीतर एक जिला न्यायालय को शामिल करेगा, जिसकी अधिकार क्षेत्र के भीतर, वाद या अन्य कार्यवाही की स्थापना के समय, मुकदमा या कार्यवाही शुरू करने वाला व्यक्ति, या जहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं, उनमें से कोई भी, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।

स्पष्टीकरण।- उप- धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति"में पंजीकृत स्वामी और पंजीकृत उपयोगकर्ता शामिल हैं।

135. उल्लंघन या पारित करने के लिए मुकदमों में राहत।–

(1) उल्लंघन के लिए या धारा 134 में निर्दिष्ट पारित करने के लिए किसी भी मुकदमे में अदालत जो राहत दे सकती है, उसमें निषेधाज्ञा (ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि अदालत उचित समझती है) और वादी के विकल्प पर, उल्लंघन करने वाले लेबल और निशान को नष्ट करने या मिटाने के लिए किसी भी आदेश के साथ या उसके बिना नुकसान या लाभ का लेखा शामिल है।

(2) उप-धारा (1) के तहत निषेधाज्ञा के आदेश में निम्नलिखित मामलों में से किसी के लिए एकपक्षीय निषेधाज्ञा या कोई अंतर्वर्ती आदेश शामिल हो सकता है, अर्थात्:-

(क) दस्तावेजों की खोज के लिए;

(बी) उल्लंघन करने वाली वस्तुओं, दस्तावेजों या अन्य सबूतों का संरक्षण जो मुकदमे के विषय से संबंधित हैं;

(ग) प्रति वादी को अपनी परिसंपत्तियों का निपटान करने या उनसे इस तरह से निपटने से रोकना जो वादी की क्षति, लागत या अन्य आर्थिक उपचारों की वसूली करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो अंततः वादी को दिए जा सकते हैं।

(3) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायालय नुकसान के रूप में (नाममात्र के नुकसान के अलावा) या किसी भी मामले में लाभ के कारण राहत नहीं देगा-

(ए) जहां ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए एक मुकदमा में, उल्लंघन की शिकायत एक प्रमाणन ट्रेडमार्क या सामूहिक मार्क के संबंध में है; या

(ख) जहां उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी अदालत को संतुष्ट करता है -

(i) कि जिस समय उसने मुकदमे में शिकायत किए गए व्यापार चिह्न का उपयोग करना शुरू किया, वह अनजान था और उसके पास यह विश्वास करने का कोई उचित आधार नहीं था कि वादी का व्यापार चिह्न रजिस्टर पर था या वादी एक पंजीकृत उपयोगकर्ता था जिसका उपयोग अनुमत उपयोग के माध्यम से किया जा रहा था; और

((ख) जब उसे व्यापार चिह्न में अभियोक्ता के अधिकार के अस्तित्व और प्रकृति के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में व्यापार चिह्न का उपयोग करना बंद कर दिया जिनके संबंध में वह पंजीकृत था; या

(ग) जहां पारित करने के लिए एक मुकदमे में, प्रति वादी अदालत को संतुष्ट करता है-(i) जिस समय उसने मुकदमे में शिकायत किए गए व्यापार चिह्न का उपयोग करना शुरू किया था, वह अनजान था और यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं था कि अभियोक्ता का व्यापार चिह्न उपयोग में था; और

(ii) जब उसे वादी के व्यापार चिह्न के अस्तित्व और प्रकृति के बारे में पता चला तो उसने तुरंत शिकायत किए गए व्यापार चिह्न का उपयोग करना बंद कर दिया।

(11) धारा 51 और 52 उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनमें कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है और विभिन्न कृत्यों को सूचीबद्ध करती है जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(12) कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा62, कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्रदत्त कॉपीराइट के उल्लंघन के समर्थन में मुकदमों और दीवानी कार्यवाही से संबंधित है।

धारा62 इस प्रकार है:-

"62. (1) इस अध्याय के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर न्यायालय की अधिकार क्षेत्र।

(i) किसी भी कार्य में कॉपीराइट के उल्लंघन या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के संबंध में इस अध्याय के तहत उत्पन्न होने वाला प्रत्येक मुकदमा या अन्य दीवानी कार्यवाही अधिकार क्षेत्र वाले जिला न्यायालय में स्थापित की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, "अधिकार क्षेत्र रखने वाला जिला न्यायालय", सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उस स्थानीय सीमा के भीतर एक जिला न्यायालय को शामिल करेगा, जिसकी अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, वाद या अन्य कार्यवाही की स्थापना के समय, मुकदमा या अन्य कार्यवाही शुरू करने वाला व्यक्ति या जहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं, उनमें से कोई भी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।"

(13) ऊपर पुनःप्रस्तुत किए गए प्रावधानों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 134 उस जिले की व्याख्या करती है जिसके पास पंजीकृत व्यापार चिह्न के उल्लंघन या पंजीकृत व्यापार चिह्न में किसी भी अधिकार के लिए प्रासंगिक या प्रतिवादी द्वारा उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यापार चिह्न के मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा जो वादी के व्यापार चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है, चाहे वह पंजीकृत हो या अपंजीकृत।कॉपीराइट

अधिनियम की धारा 62 किसी भी अन्य कार्य में कॉपीराइट के उल्लंघन या कॉपीराइट अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के मामलों में जिला न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 134 (2) में उपयोग किया गया शब्द शामिल है, और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 62 (2) इस तथ्य का संकेत है कि धारा 134 (2) और धारा 62 (2) के तहत निर्धारित जिला न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित अधिकार क्षेत्र से अधिक व्यापक है।ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 134 (2) और कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 62 (2) की भाषा समान सामग्री और है।

आर. एच. प्रयोगशालाएँ और एक और बनाम राजीव मुकुल 777
एकल स्वामी। (न्यामूर्तिएम. एम. एस बेदी)

भारतीय राजपत्र में दिनांक 1 में प्रकाशित संयुक्त समिति की रिपोर्ट को निकालना प्रासंगिक होगा, जो धारा 62 (2) से पहले और इसकी नींव रखने के लिए निम्नानुसार है:-

> "समिति की राय में कई लेखकों को उल्लंघन की कार्यवाही शुरू करने से रोका जाता है क्योंकि जिस न्यायालय में ऐसी कार्यवाही शुरू की जानी है, वह उनके सामान्य निवास स्थान से काफी दूरी पर स्थित है।समिति महसूस करती है कि इस बाधा को दूर किया जाना चाहिए और नए उपधारा(2) में तदनुसार प्रावधान किया गया है कि उल्लंघन की कार्यवाही जिला न्यायालय में उस स्थानीय सीमा के भीतर शुरू की जा सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही शुरू करने वाला व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है, व्यवसाय करता है आदि।"

(14) भारत के राजपत्र में दिनांक 23.11.1956 में प्रकाशित संयुक्त समिति की उपरोक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सफार एसए और अन्य बनाम यूफार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड और **अन्य (2), निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:-**

> "इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा62 की उप-धारा(2) को लागू करने का उद्देश्य और कारण कॉपीराइट के मालिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से

रोकना नहीं था, बल्कि उनके ऐसा करने में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करना था।धारा62 (2) को जिला न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को केवल उन मामलों तक सीमित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है जहां मुकदमा या अन्य कार्यवाही शुरू करने वाला व्यक्ति, या जहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं, उनमें से कोई भी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है या वर्तमान में लाभ के लिए काम करता है।यह संहिता की धारा20 में निर्धारित 'सामान्य' आधारों के अलावा किसी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए एक अतिरिक्त आधार निर्धारित करता है।"

(15) उक्त निर्णय में यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि धारा 62 (2) सी. पी. सी. की धारा 20 में निर्धारित सामान्य आधार के अलावा किसी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए एक अतिरिक्त आधार को प्रतिबंधित करती है।

---

(2) 2004 आकाशवाणी (अनुसूचित जाति) 1682

(16) अधिकार क्षेत्र की सीमा से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 इस प्रकार है:-

"20. जहां प्रतिवादी रहते हैं या वाद हेतु समर्थ कारण उत्पन्न होता है, वहां स्थापित किए जाने वाले अन्य मुकदमे -

उपर्युक्त सीमाओं के अधीन, प्रत्येक मुकदमा न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर -

(क) प्रतिवादी, या प्रत्येक प्रतिवादी जहां एक से अधिक हैं, मुकदमे के शुरू होने के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं; या

(ख) प्रतिवादी में से कोई भी, जहां मुकदमे के प्रारंभ के समय एक से अधिक हैं, वास्तव में रहते हैं और स्वेच्छा से, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं, बशर्ते कि ऐसे मामले में या तो न्यायालय की अनुमति दी जाती है, या प्रतिवादी जो नहीं रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसी संस्था में सहमत होते हैं; या

(ग) वाद हेतु समर्थकारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है।

[स्पष्टीकरण]।—एक निगम को भारत में अपने एकमात्र या प्रमुख कार्यालय में या किसी भी स्थान पर उत्पन्न होने वाली वाद हेतु समर्थकारण संबंध में, जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान पर व्यवसाय करने वाला माना जाएगा।

(17) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 62 (2) और धारा 134 (2) के साथ-साथ सी. पी. सी. की धारा 20 को मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा विप्रो लिमिटेड बनाम औषध चंद्रिका आयुर्वेदिक इंडिया (पी) लिमिटेड (3), जिसमें यह था के मामले में विचार में लिया गया था।

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

"11. जहां वादी का यह तर्क है कि वे किसी ऐसे न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यवसाय का प्रमुख स्थान या इसकी शाखा या शाखाएं जहां इसका व्यवसाय किया जाता है, प्रतिवादी हैं।

---

(3) 2008 (3) सीटीसी 274

कहता है कि यह व्यवसाय का प्रमुख स्थान है यह महत्वपूर्ण है। प्रतिवादियों के अनुसार, यह कॉपीराइट अधिनियम की धारा 62 (2) और ट्रेड मार्क्स अधिनियम की धारा 134 (2) की एकमात्र उचित व्याख्या है, और इसलिए, क्योंकि वादी का मुख्य

कार्यालय बैंगलोर में है, अकेले बैंगलोर में अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा।कॉपीराइट अधिनियम की धारा 62 (1) उल्लंघन कार्यवाही आदि की स्थापना के लिए मंच को जिला न्यायालय के रूप में निर्धारित करती है। धारा 62(2) में प्रावधान है कि शब्द अधिकार क्षेत्र रखने वाला न्यायालय" सी.पी.सी. या किसी भी उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद उस स्थानीय सीमा के भीतर एक जिला न्यायालय को शामिल करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर व्यक्ति या व्यक्तियों में से एक वाद को स्थापित करने वाला वास्तव में या स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत कार्य व्यापार चिन्ह अधिनियम में धारा 134 अन्तस्थापित करके विधायिका ने व्यापार चिन्ह अधिनियम को कॉपीराइट अधिनियम में चिन्ह कानून के अनुरूप बनाया है जैसा की अक्सर एक व्यापार चिन्ह भी कॉपीराइट के तहत एक कलात्मक कार्य के रूप में भी पंजीकृत **होता** है। मुकदमा ट्रेड मार्क विधायिका ने अधिनियम की धारा 134(2) को शामिल करने, डालकर ट्रेड मार्क्स अधिनियम, विधायिका ने कानून को कॉपीराइट अधिनियम के तहत एक कलात्मक कार्य के रूप में पंजीकृत होता है। कॉपीराइट अधिनियम, की धारा 62(2) के साथ साथ ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 134 (2) में, सी. पी. सी. की धारा 20 से जानबूझकर विचलन किया गया है, ताकि वादि उस व्यक्ति पर अदालत में मुकदमा कर सके जिसने उसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर उसने मुकदमा या अन्य कार्यवाही की स्थापना के समय व्यवसाय किया था।यदि "वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है"और "व्यवसाय करता है"नामक दो अभिव्यक्तियों के बीच के अंतर को सही ढंग से समझा जाता है, तो यह पता चलेगा कि निवास के संबंध में सीमा है, लेकिन "व्यवसाय करने"के संदर्भ में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।यह एक स्पष्ट संकेत है कि "व्यवसाय करता है"शब्द केवल व्यवसाय के प्रमुख स्थान तक ही सीमित नहीं है।यदि विधानमंडल का उद्देश्य केवल प्रमुख स्थान का अर्थ करना था, तो यह "व्यवसाय करता है"अभिव्यक्ति को उपयुक्त रूप से योग्य बनाता।उपरोक्त अभिव्यक्ति का स्पष्ट अर्थ

केवल यह बताता है कि जहाँ भी कोई व्यावसायिक गतिविधि होती है-चाहे वह प्रमुख स्थान हो या शाखा या शाखाएँ-पार्टी को ऐसे सभी स्थानों पर व्यापार करने के लिए कहा जाता है।"

(18) ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 134 प्रक्रियात्मक प्रकृति की है और उक्त धारा को शामिल करने का उद्देश्य ट्रेडमार्क से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों का समर्थन करना था ताकि वे प्रतिवादी के स्थान पर जाने और वहां मुकदमा दायर करने के बजाय अपने स्थान पर मुकदमा दायर कर सकें।सी. पी. सी. की धारा 20 का दायरा ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 134 (2) और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 62 (2) द्वारा बढ़ाया गया है।

(19) वादी-प्रतिवादी के वाद का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रतिवादी संख्या 1, विपणन में लिप्त है और कॉपीराइट अधिनियम के तहत वादी प्रतिवादी के अधिकारों के उल्लंघन के अलावा, करनाल जिले में विवादित व्यापार चिह्न OMEEZY का निर्यात कर रहा है। आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर वाद की अस्वीकृति के लिए एक आधार नहीं माना जा सकता है जैसा कि यूफार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड और अन्य (ऊपर) के मामले में माना गया है।

(20) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि निचली अदालत ने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर शिकायत को खारिज करने की मांग की गई है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि करनाल के जिला न्यायालयों, जिनके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति यानी वादी अपना व्यवसाय करता है, के पास ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 134 (2) और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 62 (2) के अनुसार मुकदमे का मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(21) पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देने के लिए कोई आधार नहीं बनताहै।

(22) बर्खास्त कर दिया।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी

व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)